





# सावन का अनितम सोमवार आज, हाइवे पर उमड़े कांवड़िये



शाह टाइम्स संवाददाता,  
गजरोहा। भगवान शिव की भक्ति को समर्पित माने जाने वाले सोमवार माह के चौथे व अंतिम सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। चाकेश्वर मंदिर पर सर्वाधिक पीढ़ी देखने को मिलेगी, पुलिस ने मंदिरों पर भी सुक्षम व्यवस्था बनाई ही। वहाँ रविवार को दिन भर हाइवे से होकर कांवड़ियों के जर्थे गुजरते रहे। पैदल रविवार को उत्तम कांवड़ियों के साथ साथ डाक कांवड़ियों की भी कांवड़ियों से संख्या देखने को मिली।

## आत्मा

चाकेश्वर मंदिर पर रहें वाले सोमवार माह के चौथे व अंतिम सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। चाकेश्वर मंदिर पर सर्वाधिक पीढ़ी देखने को मिलेगी, पुलिस ने मंदिरों पर भी सुक्षम व्यवस्था बनाई ही। वहाँ रविवार को दिन भर हाइवे से होकर















## चुनावी साख का सवाल

एसआईआर को लोकर न चुनाव आयोग पीछे हटाना दिखाई दे रहा है न विपक्ष, संसद भी टप पड़ी हुई है। वहां पर कोई कार्रवाही नहीं हो रही, क्योंकि जो विपक्ष चाहता है उस प्रक्रिया पर स्वतंत्र रूप से बहस हो, तो वहीं सत्ता पक्ष चुनाव आयोग को निष्पक्ष संस्था बताकर बहस से पल्ला झाड़ रहा है, उसका कहना है कि चुनाव आयोग एक सर्वेधारिक स्वतंत्र संस्था है, उसके ऊपर संसद में बहस नहीं हो सकती। बड़ी अजीबगरीब गुरुथी उलझी हुई है। इससे स्थिति और जटिल होती जा रही है। कांग्रेस ने एवं संसद भी टप पड़ी हुई है।

कांग्रेस का यह कहना कि चुनाव आयोग किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इस पर चाचों हो सकती बोकी बात है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पीप्पम और सरकार करते हैं, तो ऐसे में जबाबदी भी बनती है। उनका कहना है कि जब विपक्ष यह चाहता है कि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर संसद में चर्चा हो तो सरकार क्यां टाल मटोल कर रही है। जहिर है इससे जनता के मन में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह फैला होता है। बात बिल्कुल सही है, अधिकर जब विपक्षी दलों और जनता को ही भरोसा चुनाव आयोग पर नहीं रहेगा, तो उसके द्वारा कराए गए चुनाव के आयोग पर जनता के सिवायास कर पाएगा। निश्चित रूप से इस तह के हालात से जो स्थिति पैदा होगी वह हालांकार लोकतंत्र के लिए बेहद घातक हो सकती है। इस तरह की बातों से लोकतंत्र कदापि मजबूत नहीं होता। भले ही हम इस बात का दंभ भरते रहें कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र की साथ इस तरह की बातों से बुरी तह प्रभावित होती है। देखने में भी आ रहा है कि चुनाव आयोग कुछ वास्तु से उस तह काम नहीं कर रहा है जिस तरह एक लोकतांत्रिक देश में करना चाहिए। और अब वहां तो हालात ऐसे हो चले हैं कि चुनाव आयोग और तमाम विपक्ष सङ्कट से लेकर संसद और संसद से लेकर कोई तक हल्ला काटे हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी बात से टस से महस होता दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकर कोई भी प्रक्रिया कितनी भी अच्छी और मजबूत क्यों न हो, अगर उसमें लोगों का भरोसा नहीं है तो उसकी अच्छाई और मजबूती का कोई भल लब नहीं रह जाता। चुनाव आयोग को यह समझना ही होगा। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह तमाम राजनीतिक दलों में लेकर आगे बढ़ न कि उनसे उलझे। कोई भी अकेला आदमी सुखुम्बुल ठीक नहीं कर सकता, सबके सहयोग से ही ठीक किया जा सकता है। चुनाव आयोग को किसी का भी प्रतिदंड नहीं बनाना चाहिए। यहीं बात सरकार पर भी लागू होती है। सरकार चलाना और चुनाव प्रक्रिया दोनों अलग चीजें हैं। संविधान ने उसे सरकार से पृथक शक्ति इसलिए ही दी थी, ताकि वह किसी के दबाव में काम न करे। आज सबकुछ उलझ हो रहा है। सबसे बड़ी खासीं तो उस चुनाव प्रक्रिया में आ गई, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। जिस तरह सुप्राप्त कार्ट के मुख्य न्यायीशां को इस प्रक्रिया से बहाल किया गया, वह तभी तय हो गया था कि चुनाव आयुक्त वही बनेगा, जिसे सरकार चाहेगी।

## दुष्कर्मियों को संक्षण न दें भाजपा सरकारे

जहां भाजपा सरकार है, वहां दुष्कर्म का आंकड़ा बढ़ रहा है और भाजपा को सरकार इन अपराधों को रोकने में नाकाम हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी पीप्पम एवं डिवोडो के दुष्कर्म के आरोपी पौर ब्रज्जुल रमना के लिए प्रचार कर लाया से उसे वोट देने वाली की अपील की है, श्री मोदी संसद से भागते हैं संसद भवन में हाते पर चल ही रही गोपनीय भवन को अपराध के सिद्धान्त पर चल ही रही गोपनीय भवन को एक नाबालिग बच्चों का अपराध किया और उसे जिंदा जलाया दिया, बच्चों को दिल्ली एस्लाया गया, जहां उस 15 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया, बच्ची को जलाने वाल कहां हैं, क्या उनको गिरफतारी हुई, तो जबाब मिला कि बच्ची को जलाने में किसी का हाथ नहीं था, ये पुलिस और सरकार की नाकामी है।

-अलका लांबा, अध्यक्ष, महिला कांग्रेस



**31** र्थव्यवस्था युद्ध बन चुकी है, और कर्ज नए टैक है। यह बात सिफ्प-एक मुहावर है। वाले भी, बल्कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की उस रणनीति का सार है, जिसे दुनिया अब धो-धीरे समझ रहा है।

ट्रंप की टैरिफ थ्रेट नीति यानी जो देश चीन या ब्रिटेन की ओर बढ़के, उन पर भारी व्यापार कर लोगों ये विधियां नहीं हो रही, क्योंकि जो विपक्ष चाहता है उस प्रक्रिया पर स्वतंत्र रूप से बहस हो, तो वहीं सत्ता पक्ष चुनाव आयोग को निष्पक्ष संस्था बताकर बहस से पल्ला झाड़ रहा है, उसका कहना है कि चुनाव आयोग एक सर्वेधारिक स्वतंत्र संस्था है, उसके ऊपर संसद में बहस नहीं हो सकती। बड़ी अजीबगरीब गुरुथी उलझी हुई है। इससे स्थिति और जटिल होती जा रही है। कांग्रेस ने एवं संसद भी टप पड़ी हुई है।

कांग्रेस का यह कहना कि चुनाव आयोग किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इस पर चाचों हो सकती बोकी बात है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पीप्पम और सरकार करते हैं, तो ऐसे में जबाबदी भी बनती है। उनका कहना है कि जब विपक्ष यह चाहता है कि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर संसद में चर्चा हो तो सरकार क्यां टाल मटोल कर रही है। जाहिर है इससे जनता के मन में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह फैला होता है। बात बिल्कुल सही है, अधिकर जब विपक्षी दलों और जनता को ही भरोसा चुनाव आयोग पर नहीं रहेगा, तो उसके द्वारा कराए गए चुनाव के आयोग पर जनता के लिए विपक्ष एवं विपक्षी दलों ने एक समझौता कर रखा है। जब विपक्षी दलों ने एक समझौता कर रखा है, तो उसके द्वारा विपक्षी दलों को बदला जाएगा।

कर्ज और कब्जा-ट्रंप और यहूदी

बैंकिंग लॉबी का समझौता

स्त्रीं के अनुसार, ट्रंप ने अपनी चुनावी तैयारियों और निजी परियोजनाओं के लिए यहूदी बैंकिंग एशिया की सर्ती बैटरी से हार होती है, बिलेन की स्टील मिलें सत्ते रूसी-चीन उत्पादों से जु़ज़ रही हैं। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ रणनीति असल में बक्तव्य खरीदने की कोशिश है। अमेरिका और उनके साथी देशों के लिए अमेरिका नए उत्पादन बहाल कर रही है, लेकिन यहूदी की अधिकारी घरेलू बाजार की मरणाई ट्रंप की नीति का सबसे आमधारी परिणाम साथित हो रही है, जिसका आर्थिक व राजनीतिक नुकसान अमेरिका को ही ज्ञाला रखा है।

स्त्रीं और लॉबी के समझौता

स्त्रीं के अनुसार, ट्रंप ने अपनी चुनावी तैयारियों और निजी परियोजनाओं के लिए यहूदी बैंकिंग एशिया की सर्ती बैटरी के लिए यहूदी बैंकिंग एशिया की सर्ती बैटरी से हार होती है, बिलेन की स्टील मिलें सत्ते रूसी-चीन उत्पादों से जु़ज़ रही हैं। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ रणनीति असल में बक्तव्य खरीदने की कोशिश है। अमेरिका और उनके साथी देशों के लिए अमेरिका नए उत्पादन बहाल कर रही है, लेकिन यहूदी की अधिकारी घरेलू बाजार की मरणाई ट्रंप की नीति का सबसे आमधारी परिणाम साथित हो रही है, जिसका आर्थिक व राजनीतिक नुकसान अमेरिका को ही ज्ञाला रखा है।

स्त्रीं और लॉबी के समझौता

स्त्रीं के अनुसार, ट्रंप ने अपनी चुनावी तैयारियों और निजी परियोजनाओं के लिए यहूदी बैंकिंग एशिया की सर्ती बैटरी के लिए यहूदी बैंकिंग एशिया की सर्ती बैटरी से हार होती है, बिलेन की स्टील मिलें सत्ते रूसी-चीन उत्पादों से जु़ज़ रही हैं। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ रणनीति असल में बक्तव्य खरीदने की कोशिश है। अमेरिका और उनके साथी देशों के लिए अमेरिका नए उत्पादन बहाल कर रही है, लेकिन यहूदी की अधिकारी घरेलू बाजार की मरणाई ट्रंप की नीति का सबसे आमधारी परिणाम साथित हो रही है, जिसका आर्थिक व राजनीतिक नुकसान अमेरिका को ही ज्ञाला रखा है।

स्त्रीं और लॉबी के समझौता

स्त्रीं के अनुसार, ट्रंप ने अपनी चुनावी तैयारियों और निजी परियोजनाओं के लिए यहूदी बैंकिंग एशिया की सर्ती बैटरी के लिए यहूदी बैंकिंग एशिया की सर्ती बैटरी से हार होती है, बिलेन की स्टील मिलें सत्ते रूसी-चीन उत्पादों से जु़ज़ रही हैं। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ रणनीति असल में बक्तव्य खरीदने की कोशिश है। अमेरिका और उनके साथी देशों के लिए अमेरिका नए उत्पादन बहाल कर रही है, लेकिन यहूदी की अधिकारी घरेलू बाजार की मरणाई ट्रंप की नीति का सबसे आमधारी परिणाम साथित हो रही है, जिसका आर्थिक व राजनीतिक नुकसान अमेरिका को ही ज्ञाला रखा है।

स्त्रीं और लॉबी के समझौता

स्त्रीं के अनुसार, ट्रंप ने अपनी चुनावी तैयारियों और निजी परियोजनाओं के लिए यहूदी बैंकिंग एशिया की सर्ती बैटरी के लिए यहूदी बैंकिंग एशिया की सर्ती बैटरी से हार होती है, बिलेन की स्टील मिलें सत्ते रूसी-चीन उत्पादों से जु़ज़ रही हैं। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ रणनीति असल में बक्तव्य खरीदने की कोशिश है। अमेरिका और उनके साथी देशों के लिए अमेरिका नए उत्पादन बहाल कर रही है, लेकिन यहूदी की अधिकारी घरेलू बाजार की मरणाई ट्रंप की नीति का सबसे आमधारी परिणाम साथित हो रही है, जिसका आर्थिक व राजनीतिक नुकसान अमेरिका को ही ज्ञाला रखा है।

स्त्रीं और लॉबी के समझौता

स्त्रीं के अनुसार, ट्रंप ने अपनी चुनावी तैयारियों

